

एक नजर

आईएमए की लंबित मांगों पर सरकार की मुहर, पर प्रस्नता

—भारतीय बस्ती संवाददाता—
बस्ती। इंडियन मेडिकल एसोसियेशन उप्र. की लंबित मांगों का जैसे ही सरकार ने स्वीकार किया है वही जिले के प्रांत पत्रकारियों में बड़े का माहौल हो गया। प्रदेश अख्य डॉ. अनिल श्रीवास्तव ने बताया कि विगत छह वर्षों से गुप्त रखने एवं प्रत्येक बड़े होने वाले सीएमए रजिस्ट्रेशन को हटा कर बार-बार पर किए जाने की मांग की जा रही थी।
उक्त मांगों को सरकार द्वारा स्वीकृत किया जाने पर सभी ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया है। एसोसियेशन ने यह विषय दिलाया कि सरकार द्वारा प्राप्त निर्देशों का पालन होगा।

यात्री छाजन से बुजुर्गों का शव बरामद

—भारतीय बस्ती संवाददाता—
बस्ती। कवारी थानाक्षेत्र के कलसरी मुख्यालय गांव के पास बने यात्री छाजन में सुबह एक बुजुर्ग का शव शव मिला। सुचना पर पहुंची पुलिस ने शव काबू में लेकर पश्चात का प्रयास कर लिया। दोपहर बाद मृतक को रिमाउंड रिजुइन पांडेय निवासी कलसरी मुख्यालय के रूप में उद्धार। अगली सुबह पुलिस ने विज्ञापन प्रकाशित करने के बाद शव काबू में लिया गया तब तक उनकी पहचान नहीं हो सकी थी। कुछ लोगों ने बताया कि मृतक कलसरी के ही रहने वाले है उनका नाम रिजुइन पांडेय है। पुरुषाचल में पता चला कि उनके परिवार के सभी सदस्य अपनी कुल संपत्ति बेचकर बहुत पहले ही गांव छोड़ कर चले गए हैं। सब काफ है, इसकी कोशिश जानकारों ने है।
(निम्नलिखित विवरण) घर पर कुछ नहीं बचने के कारण आसपास के बाजारों में नाच की दुकानों पर दिन में कार्य में मदद कर रही छा पीकर से जालें बंधे। एक जगह वे प्यादा दिन से लकी नहीं रहते थे। प्रातः पांच दिनों से यात्री छाजन के आस पास उन्हें देखा जा रहा था। पुलिस ने शराब को कब्जे में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

ठेकेदार की जर्जर दीवार

के मलबे में दबकर मौत
—भारतीय बस्ती संवाददाता—
बस्ती। लालजग थानाक्षेत्र के ककरौली गांव में ठेका पर जर्जर दीवार गिराने का काम करते वक दोपहर एक व्यक्ति मलबे के नीचे दब गया। जब तक उसे बाहर निकाला जाता, रात को चार आने के कारण मौत पर ही मौत हो गई। सुचना मिलते ही मृतक के परिजन मौक पर पहुंच गए। उनके घर लेकर बंध गए। बताया जा रहा है कि थानाक्षेत्र के विचारधारा निवासी अशर्मा (60) पुत्र रामनिवास ने ककरौली की क बटुन नाल के पुराने घर को ढहाने का ठेका लिया था।

किसान सम्मान निधि के लिये फार्म रजिस्ट्री अनिवार्य

बस्ती। किसान सम्मान निधि प्राप्त करने के लिये किसानों को अपनी फार्म रजिस्ट्री तैयार करना हेतु शासन द्वारा अनिवार्य कर दिया गया है। उक्त जानकारी देते हुए संयुक्त निदेशक कृषि एम. विहारी ने बताया कि फार्म रजिस्ट्री में प्रत्येक व उसके पिता का नाम, उसका स्थायित्व वाले सभी गाटा सं. 80, सहस्रवत्सवार होने की तिथि में गाटा में किसान का नाम, मोबाइल नम्बर, आधार कार्ड संख्या एवं ई-केवाई. सी. की विवरण दर्ज किया जाएगा। फार्म रजिस्ट्री तैयार होने के बाद उन्हें सिर्फ 60000 किसान सम्मान निधि ही नहीं, बल्कि ककरौली, धरमल बीमा, एमएचएलसी, उर्वरी योजनाओं का भी लाभ प्राप्त होगा।

एग्जिट पोलस: महाराष्ट्र में भाजपा गठबंधन भारी, झारखंड में छिन रहा हेमंत सोरेन का ताज



नई दिल्ली (आभा)। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान समाप्त हो गया और अब एग्जिट पोल के नतीजे भी आने लगे हैं। महाराष्ट्र में एग्जिट पोलस ने भाजपा के नेतृत्व वाले महायुक्ति गठबंधन को टाइट फाइट में बढ़त दिखाई है। वहीं झारखंड में भाजपा अपने दम पर बहुमत की ओर बढ़ रही है। पीपल्स पर्स, डंडातम, पी-मार्क और न्यूज 24-पी मार्क के सर्वे में महायुक्ति की महाराष्ट्र में सरकार बन रही है।
पी-मार्क के अनुसार महाविकास अघाड़ी को 126 से 146 सीटें हासिल हो सकती है। इस तरह पी-मार्क ने भाजपा गठबंधन को बढ़त दिखाई है, जबकि कांग्रेस की लीडरशिप वाले महाविकास अघाड़ी को 97 सीटें ही मिलने का अनुमान है। वहीं अन्य के खाल में 9 सीटें जा सकती हैं।

वोटर कार्ड चेक कर रहे पांच पुलिसकर्मी निलंबित



लखनऊ (आभा)। यूपी की नौ सीटों पर हो रहे उपचुनाव में भाजपा-बजपा के बीच भी संभावना है कि शिकायत पर निवेदन आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है। दोष कर चेक करने की शिकायत पर पांच जमीनी विवाद में दबाओं ने मारा पीटा: दलित ने एसपी से लगाया न्याय की गुहार

कहा है कि गत 18 नवंबर की शाम को गांव के ही अविद्वेष चौधरी पुत्र राम सुत, नितराम पुत्र पुनई, सुनील पुत्र नितराम, कचन पुत्र नितराम, लक्ष्मी पत्नी लवकुश आदि उसके दरवाजे पर चढ़ आये और जाति सूचक भददी-भददी गालियां देकर मारा पीटा। उसे और उसके बिकलांग भाई प्रीतम, भाभी नीलम व किरन को बुरी तरह से मारा पीटा। रामलाल का फिर फट गया। 12 नवंबर पर फोन करने पर कप्तानगुप्त पुलिस पहुंची दोषियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने की जगह उसे और रामलाल के परिवार का शक्ति भंग में चालान कर दिया।



—भारतीय बस्ती संवाददाता—
बस्ती। जमीनी विवाद और रंजिश को लेकर भारतीय के मामले में कप्तानगुप्त पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज न किये जाने को लेकर कप्तानगुप्त थाना क्षेत्र के सेफुद्धा निवासी दलित रामलाल पुत्र ओम प्रकाश ने पुलिस अधीक्षक पर पत्र देकर न्याय की गुहार लगाया है। एसपी को दिये पत्र में रामलाल ने

बहुमत की ओर दिखाया गया है। इस सर्वे में भाजपा को 152-160 सीटें मिलने की भविष्यवाणी है। इसके अलावा 130-138 सीटें अघाड़ी के खाल में जा सकती है। राज्य में 6 से 8 सीटें अन्य को मिलने की बात कही गई है।
अब झारखंड की बात करें तो यहां भी भाजपा को स्पष्ट बहुमत का ही अनुमान है। Matriz के अनुसार भाजपा और आजगुप्त गठबंधन को 42 से 47 सीटें मिल सकती हैं। इसके

रिवाल्वर लेकर वोटरों को धमकाते दिखे थाना प्रभारी: 7 पुलिसकर्मी निलंबित



लखनऊ (आभा)। यूपी के नासना चुनाव का समीक्षाफल माने जा रहे उपचुनाव को लेकर संभावना पार्टी लगातार यूपी पुलिस को निषाण पर लिए हुए है। सारी की शिकायत पर ही चुनाव आयोग ने सतत पुलिस वालों को अब तक निलंबित किया है। अखिलेश यादव ने एक और वीडियो एक्स पर पोस्ट करते हुए मुजरकरनगर के ककरौली थाना प्रभारी पर रिवाल्वर लेकर वोटरों को धमकाने का आरोप लगाया है। चुनाव आयोग को एएसपी को तत्काल निलंबित करने की मांग भी कर दी है। अखिलेश ने एएसपी पर वीडियो के साथ लिखा कि मीरापुर के ककरौली थाना क्षेत्र के एएसपी को चुनाव आयोग दुरंत निलंबित करें। यो रिवाल्वर से 6 मकानकर वोटर्स को बोट डालने से रोके रहे हैं।

अखिलेश ने जो 22 सेकेंड का वीडियो पोस्ट किया है उसमें दिख रहा है कि ककरौली के एएसपी को



—भारतीय बस्ती संवाददाता—
बस्ती। सदी सदर तहसील क्षेत्र के कवरा निवासी संजय शर्मा ने जिलाधिकारी को पत्र देकर मुमि का सीमांकन करवाने की मांग किया है। डीएम को दिये पत्र में संजय शर्मा ने कहा है कि सर्वे लेखाल की आख्या के आधार पर उप

जिलाधिकारी सदर ने ग्राम गंगपुर तपा बरकला परगना महुली पश्चिम तहसील सदर बस्ती के आधार वर्ष खतीनी संख्या 762 के गाटा संख्या 2109/1 के सीमांकन हेतु राजस्व टीम का गठन किया था।

राजस्व टीम में दिनेश तिवारी राजस्व निरीक्षक विनोदपुर, राम हरख क्षेत्रीय सर्वे लेखाल, दिलीप पटेल, विकास राजस्व लेखाला को प्रकरण के निराकरण का निर्देश दिया गया था। अमी तज जमीन की पमाइश नहीं किया गया। संजय शर्मा ने डीएम को दिये पत्र में कहा है कि अनेकों बार पत्र दिये जाने के बावजूद आम तज जमीन का सीमांकन नहीं किया गया। मांग किया कि जमीन का सीमांकन करकर प्रकरण का निराकरण कराया जाय।

यूपी उपचुनाव: एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त

लखनऊ (आभा)। यूपी उपचुनाव में वोटिंग पूरी होने के बाद एग्जिट पोल भी आने लगे हैं। जी न्यूज आईसीपीएल एग्जिट पोल के अनुसार यूपी की नौ सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा को बढ़त मिलती दिख रही है। भाजपा नौ में से बार से छह सीटें जीत सकती है। वहीं समाजवादी पार्टी को तीन से पांच सीटें मिलती दिख रही हैं। हालांकि दोनों ओर से नौ में से नौ सीटें जीतने का दावा किया गया था। अब ऐसी स्थिति नहीं दिख रही है। फिलहाल नौ में से भाजपा के पास पांच और सपा के पास चार सीटें हैं। इस तरह से देखें तो अगर एग्जिट पोल ही रिजल्ट में परिवर्तित होते हैं तो भाजपा को अति कम एक सीट का फायदा हो रहा है।

यूपी उपचुनाव में नौ विधानसभा सीटें भीमपुर, कुन्दकी, गाजियाबाद, खैर (आभा), कहरल, सीसाऊ, फूफुर, कटहरी और मझवा के नासना सपा पर मतदान पुरा हो चुका है। नौ सीटों पर कुल 90 प्रत्यक्ष चुनाव मैदान में हैं, जिनके माध्यम का फैसला होगा।

पीड़ित निषाद परिवार को न्याय दिलाने की मांग: सौपा ज्ञापन

—भारतीय बस्ती संवाददाता—
बस्ती। कुवार को भारत मुक्ति मोर्चा जिलाध्यक्ष आर.के. आरतिथि और निर्वल इण्डियन शोषित हमार आम दल निषाद पार्टी संघटन के नेतृत्व में नेताओं और नागरिकों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौपा। मांग किया कि कप्तानगुप्त थाना क्षेत्र के बेलाजोर निवासी सीतापति निषाद पत्नी राम बहने निषाद का जमीनी मामले में उत्पीड़न बंद करवाकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के साथ ही मुकदमा पंजीकृत करवाकर उनके परिवार के जान माल की रक्षा कराया जाय।

डीएम को सौपा ज्ञापन में कहा गया है कि कप्तानगुप्त थाना क्षेत्र के बेलाजोर निवासी सीतापति निषाद पत्नी राम बहने निषाद की आबादी में 75 वर्षों से आबाद हैं। रास्ते के विवाद को लेकर गत 3 जून को दिनांक 12 बजे दुर्गा प्रसाद के परिवार के लोग कब्जा रहे थे तब उसने उपजिलाधिकारी हरिया को 6 जून को शिकायती प्रार्थना पत्र दिया था। इस पर उपजिलाधिकारी हरिया ने थानाक्षेत्र कप्तानगुप्त को सरकारी लिखा पर अब कब्जे को रोकने के लिए आदेश दिया था। थानाक्षेत्र द्वारा कब्जा करने से धनपक्षी को रोका गया था। गत 15 अक्टूबर को सुबह 8 बजे दिन में दुर्गा प्रसाद अजीत, अमिष, अनुग्रह व उसके परिवार सहित जाने से मार देने की 6 मनी दिए। सीतापति ने मामले की जांच करवाकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई और अपने परिवार के जान माल के रक्षा की गुहार लगाया है किन्तु पुलिस को प्रमाणी कार्रवाई नहीं कर रही है।

पुण्य तिथि पर याद किये गये जन कवि बालसोम गौतम

—भारतीय बस्ती संवाददाता—
बस्ती। 'ये शांति और ये फूलों का मुझाझा देव उदारीयें, जब तय है होगी सुबह, खिलेंगे फूल हजारों नये-नये' जैसी रचनाओं से समाज को संदेश देने वाले जन कवि बालसोम गौतम को उनकी आठवीं पुण्य तिथि पर याद किया गया। प्रमुख गौतम स्मृति संस्थान की ओर से कुवार को प्रेम बल्ल के समागार में आयोजित कवि सम्मेलन एवं मुशायरे में कवि, शायरों ने बालसोम गौतम के साहित्यिक योगदान पर विमर्श किया।

मुख्य अतिथि डा. वी.के. वर्मा ने कहा कि बालसोम गौतम का रचना संसार विस्तार लिये हुये हैं। वे अपने समय के सशक्त हस्ताक्षर थे, उनकी कविताएँ हमें संकेत में साहस देती हैं। डा. वर्मा ने बाल सोम पर केन्द्रित रचना 'बाल सोमजी ने जीवन में कभी न मानी हार, उनकी पुण्य तिथि पर करता नमन उन्हें शवावर' सुनोकर उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला।

बालसोम गौतम के शिष्य डॉ. राम कृष्ण लाल 'जगमग' ने कहा कि बाल सोम गौतम को याद करना इतिहास के कई बिन्दुओं को खोलने जैसा है। वे स्वयं में अस्मिता कवि थे। उन्होंने बालसोम गौतम से जुड़े अनेक प्रसंगों अनुभवों को साझा किया। उनकी कविता 'हर पल



—जी न्यूज का दावा है कि उनसे इस बार एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर एग्जिट पोल किया है। सोशल मीडिया पर लगभग एक लाख पोस्ट और कमेंट के सेंटिमेंट के आधार पर एआई की मदद से उसने सर्वे किया है। इस सर्वे में कई सवाल लोगों से पूछे गए थे।

कटेंगे तो बटेंगे और जुड़ेंगे तो जीतेंगे के नारों के बीच हुए चुनाव में माना जा रहा था कि भाजपा हिन्दुत्व को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ रही है। लोगों को जाति के आधार पर बंटने से रोकने का प्रयास किया जा रहा था। लोगों से इसे लेकर भी सवाल किए गए। चुनाव में हिन्दुत्व चला जा जाति? इस पर 40 प्रतिशत लोगों



ने कहा कि जाति के आधार पर बंट दिए जा रहे हैं। 40 प्रतिशत ने ही माना कि हिन्दुत्व के नाम पर वोट पड़ रहे हैं। 20 प्रतिशत ने माना कि दोनों दल ही बंट रहे हैं। चुनाव के बीच ही बुलडोजर को लेकर सुभिम कोर्ट का फैसला भी आया है। इसे लेकर पूछे गए सवाल पर लोगों ने नहीं कहा कि बुलडोजर इस बार मूढ़ नहीं था। कानून व्यवस्था पर लोगों ने योगी को बेहतर बताया। कानून व्यवस्था पर कौन सा सीएम बेहतर है। इस सवाल पर 55 प्रतिशत ने योगी आदित्यनाथ को बेहतर बताया। 30 प्रतिशत ने अखिलेश यादव और 15 प्रतिशत ने मायावती को कानून व्यवस्था के मामले पर बेहतर मुख्यमंत्री बताया है।



मकी दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक आदि को भेजे पत्र में सीतापति निषाद ने कहा है कि वह एवम् डीडी आबादी पुरानी सिकमी नम्बरजन में हैं जिस जमीन में उसका जमान, छपर, शौचालय, नल तथा जानवरों को खिलाने के लिए पत्थरी रखकर करीब 75 वर्षों से आबाद हैं। रास्ते के विवाद को लेकर गत 3 जून को दिनांक 12 बजे दुर्गा प्रसाद के परिवार के लोग कब्जा रहे थे तब उसने उपजिलाधिकारी हरिया को 6 जून को शिकायती प्रार्थना पत्र दिया था। इस पर उपजिलाधिकारी हरिया ने थानाक्षेत्र कप्तानगुप्त को सरकारी लिखा पर अब कब्जे को रोकने के लिए आदेश दिया था। थानाक्षेत्र द्वारा कब्जा करने से धनपक्षी को रोका गया था। गत 15 अक्टूबर को सुबह 8 बजे दिन में दुर्गा प्रसाद अजीत, अमिष, अनुग्रह व उसके परिवार सहित जाने से मार देने की 6 मनी दिए। सीतापति ने मामले की जांच करवाकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई और अपने परिवार के जान माल के रक्षा की गुहार लगाया है किन्तु पुलिस को प्रमाणी कार्रवाई नहीं कर रही है।

गौतम, ठाकुर प्रेमनन्दन, राम निषाद, रमेश चन्द्र निषाद, मुन्ना निषाद, कल्याण निषाद, हरि प्रसाद साहू, दीप निषाद, ज्ञान प्रकाश, बल्लू नारा, सन्तोष निषाद, मनोरमा निषाद, राम मनन निषाद, लालचन्द निषाद, आकाश निषाद, लक्ष्मी, अविन निषाद, बालचन्द निषाद आदि शामिल रहे।



गौतम प्रेम के गाया, नौ ही किसी का हृदय दुखाया, कौन करे अब लेखा दुखाया, जीवन में क्या खोया पाया को श्रोताओं ने सराहा। डॉ. जगमग ने बाल सोम जी की कविताओं को सुनते हुये कई प्रसंगों की विस्तार से चर्चा किया। राम नरेश सिंह मूल देवी हैं। डा. वर्मा ने बाल सोम पर केन्द्रित रचना 'बाल सोमजी ने जीवन में कभी न मानी हार, उनकी पुण्य तिथि पर करता नमन उन्हें शवावर' सुनोकर उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला।

बालसोम गौतम के शिष्य डॉ. राम कृष्ण लाल 'जगमग' ने कहा कि बाल सोम गौतम को याद करना इतिहास के कई बिन्दुओं को खोलने जैसा है। वे स्वयं में अस्मिता कवि थे। उन्होंने बालसोम गौतम से जुड़े अनेक प्रसंगों अनुभवों को साझा किया। उनकी कविता 'हर पल

कार्यशाला में दिया आयकर कटौती की जानकारी

—भारतीय बस्ती संवाददाता—
बस्ती। जिलाधिकारी रवीश गुप्ता की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयकर की जानकारी जगमग कार्यशाला का कार्यशाला सम्पन्न हुयी। कार्यशाला का सम्मोचित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि यहाँ जो भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उन्हें गम्भीरता से लिया जाय। उन्होंने कहा कि टीडीएस कटौती कम या ज्यादा पाये जाने पर वैधानिक जिम्मेदारियां तय की जायेगी। उन्होंने कहा कि टेक्स निर्धारित समयविधि में जमा करें,

बारे में आहरण-वितरण अधिकारियों और लेखा कर्मचारियों तथा वेतन, आयकर कटौती, रिटर्न दायित्व करने के संबंध में अधिकारियों को विस्तृत जानकारी प्रदान किया। उन्होंने बताया

कि टीडीएस कटौती न करने पर जुर्माना का प्रमाणन है। मुख्य कोषाधिकारी अशोक कुमार जयप्रती ने बताया कि यह अवश्य देव दिया जाय कि बिलो पर आधार व पैज दर्ज हो व आधार व पैज लिंक हो। कार्यशाला में आयकर अधिकारी विनोद कुमार सिंह, इनकम स्पेक्टर सचिन पटेल, सुपरीटेंडेंट धनंजय मिश्रा, सीएमओ डा. आर.एस. दुष्य, उप जिलाधिकारी न्यायिक मनोज प्रकाश, उपा निदेशक अशोक कुमार, गौतम सहित सं. 8 धित आहरण-वितरण अधिकारीगण उपस्थित रहे।

कि टीडीएस कटौती न करने पर जुर्माना का प्रमाणन है। मुख्य कोषाधिकारी अशोक कुमार जयप्रती ने बताया कि यह अवश्य देव दिया जाय कि बिलो पर आधार व पैज दर्ज हो व आधार व पैज लिंक हो। कार्यशाला में आयकर अधिकारी विनोद कुमार सिंह, इनकम स्पेक्टर सचिन पटेल, सुपरीटेंडेंट धनंजय मिश्रा, सीएमओ डा. आर.एस. दुष्य, उप जिलाधिकारी न्यायिक मनोज प्रकाश, उपा निदेशक अशोक कुमार, गौतम सहित सं. 8 धित आहरण-वितरण अधिकारीगण उपस्थित रहे।

"मुझे अखबार निकालने दो तो मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"—वेडेल फिलिपा

भारतीय बस्ती

बस्ती 21 नवम्बर 2024 गुरुवार

सम्पादकीय

मणिपुर में बंदी मुश्किलें

कभी शांतिप्रिय माने जाने वाले मणिपुर में बीते डेढ़ साल से जारी हिंसा एक गंभीर चुनौती बनती जा रही है। राज्य में नए सिर से शुरू हुई अमानवीय हिंसा व आगजनी की घटनाएं स्थिति की गंभीरता को दर्शाती हैं। इस हिंसाग्रस्त पूर्वोत्तर के हालात से निपटने में केंद्र और राज्य सरकार बेबस और उदासीन नजर आ रहे हैं। हाल के दिनों में पन्नी गंभीर हिंसा की घटनाएं राज्य नेतृत्व की क्षमताओं पर सवाल उठाती हैं। केंद्र व राज्य में एक ही दल की सरकार होने के बावजूद हिंसा न थमने को लेकर विषम लगातार सवाल उठाता रहा है। निश्चित रूप से यह गंभीर स्थिति ही है कि दो सौ से अधिक लोगों के मारे जाने तथा हजारों लोगों को विस्थापन के बावजूद संकट का समाधान होता नजर नहीं आ रहा है। यही वजह है कि इन घटनाओं के बाद जनक्रोध सड़कों पर नजर आ रहा है। राज्य में कई विधायकों के घरों पर हमले व आगजनी की घटनाएं हुई हैं। यहां तक कि साठ सदस्यीय विधानसभा में साठ सदस्यों वाली नेशनल पीपुल्स पार्टी यानी एनपीपी ने राज्य सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। पार्टी का आरोप है कि मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार संकट का समाधान निकालने तथा सामान्य स्थिति बहाल करने में पूरी तरह से विफल रही है। हालांकि एनपीपी के समर्थन वापस लेने से सरकार को कोई सलाह नहीं है क्योंकि सरकार के पास विधानसभा में पर्याप्त बहुमत है, लेकिन घटनाक्रम स्थिति की गंभीरता को जरूर दर्शाता है। साथ ही घटनाक्रम सत्तारूढ़ भाजपा को चेताना है कि वह अब हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकती। हालांकि, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने राज्य में दो दिन के दौरान सुखशा स्थिति की समीक्षा जरूर की है। वहीं मुख्यमंत्री ने भी सत्तारूढ़ गठबंधन के मंत्रियों और अन्य विधायकों से बैठक करके उन्हें समझाने की कोशिश की है।

विषम मणिपुर के बेहद चिंताजनक हालात होने के बावजूद प्रधानमंत्री की अपेक्षित सक्रियता न होने का आरोप संसद से सड़क तक लगाता रहा है। वे आरोप लगाते रहे हैं कि पूरी दुनिया की खैर-खबर लेने वाले प्रेस मणिपुर में गिरफ्तार नहीं जाते। साथ ही उनका आरोप है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय लगातार बिगड़ती स्थिति को नियंत्रित करने में विफल रहा है। सवाल यह भी कि सुखशा बलों की निरंतर बढ़ती उपस्थिति के बावजूद स्थितियां नियंत्रण में क्यों नहीं आ रही हैं। यह भी कि लगातार वन व चोपट होती कानून व्यवस्था के बाद भी कैसे पार्टी मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह पर बरफोला जता रही है। उनकी फिलताओं के बावजूद उनको हटाने की मांग को क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है। वह भी तब जबकि आक्रोशित जनता पार्टी विधायकों के घरों को आगजनी से निशाना बना रही है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पूर्वोत्तर का यह राज्य संवेदनशील अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा है। मणिपुर की हिंसा बीते साल मई में मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग के बाद शुरू हुई थी। जिसका राज्य के कुकी व नागा समुदाय ने हिंसक विरोध किया था। लेकिन यह गंभीर बात है कि पिछले डेढ़ वर्षों में राज्य के भीतर अवैध प्रवास, जमीन, जंगल, हथियारों की तस्करी व नशे के कारोबार में खासी तेजी आयी है। यहां तक कि म्यांमार से अवैध घुसपैठ की घटनाएं भी सामने आई हैं। निरसंदेह, इस संकट के तमाम आयाम हैं, जिसकी संवेदनशीलता को देखते हुए इस मामले के शीघ्र समाधान की जरूरत महसूस की जा रही है। संकट इस बात का भी है कि यह संघर्ष पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में भी फैल सकता है। हाल के वर्षों में म्यांमार व बांग्लादेश में बदले राजनीतिक घटनाक्रम के चलते पृथक्तावादियों को शह मिल सकती है, जो कालांतर में भारत में कानून व्यवस्था के लिये संकट पैदा कर सकते हैं। यदि हम पूर्वोत्तर के इतिहास पर नजर डालें तो पाते हैं कि पूर्वोत्तर में सामुदायिक संरचना बेहद जटिल और संवेदनशील रही है। इससे हिंसा का सिलसिला लंबा खिंच सकता है। ऐसे में केंद्र व राज्य सरकार की कोशिश हो कि संकट का राजनीतिक व सामाजिक समाधान निकाला जाए ताकि समुदायों में सामंजस्य से हिंसा को टाला जा सके।

तंत्र का यंत्र बनते चुनाव और लोकतंत्र

—योगेन्द्र यादव—

इस साल चुनाव देखने-दिखाने, सुनने-बतियाने तथा लड़ने-लड़ाने हुए मुझे 40 बरस पूरे हो जाएंगे। मुझे याद है 1984-85 का वह अमृतपूर्व चुनाव, जिसमें राजीव गांधी की चुनावी अंजी ने सब भविष्यवाणियों को झुल्ला दिया था। उस चुनाव में प्रणय रॉय द्वारा इंडिया टुडे पत्रिका में किए विश्लेषण को पढ़कर मेरी चुनावी विश्लेषण और भविष्यवाणी में दिलचस्पी जगी थी।

पिछले चार दशकों में चुनावों के दौरान देश और दुनिया के अलग-अलग कोनों की घूल फांकने का मौका मिला, अखबार, टीवी और अब यूट्यूब पर विश्लेषण किया है, एक बार खुद चुनाव लड़ने और कई बार चुनाव लड़ाने का अवसर भी मिला है। जब पीछे मुल्ला देखा हू तो लगता है चुनाव का शाब्दिक और कानूनी चेहरा भले ही यही रहा है, लेकिन चुनाव नामक इस घटना का स्वरूप बुनियादी रूप से बदल गया है। मुझे याद है 1994 में जब मुझे जमीनी के चुनाव देखने का मौका मिला, तब आंखों में धुमा था कि वह सड़कों पर, बाजार में, होटल में और यहां तक कि अखबार के पन्नों पर भी कहीं चुनाव का कोई माहौल ही नहीं था। उस दिनों तक भारत के चुनाव एक सेले जैसे हुआ करते थे। दीवार लेखन, पोस्टर, बैनर, झंडियों की लड़ियां या फिर बड़े-बड़े झंडे। इनसे पूरा शहर घटा



रहता था, चुनाव चल रहे हैं इसका आख खोलने भर से पता रहता था। पब्लिक को कुछ तकलीफें जरूर होती थी, जैसी हर त्योहार में होती हैं। लेकिन कुल मिलाकर यह लोकोत्सव होता था, जिसमें रौनक थी, जनता के जनार्दन होने की खनक थी। अब चुनाव आयोग की तरफ से ही नाना प्रकार की बर्दशें लग गई हैं, सड़क से पोस्टर, बैनर, झंडियां लगना गायब हो चुकी हैं। कभी अखबार में बड़ा विज्ञापन दिख जाता है, बस। चुनाव प्रचार घर की चारदीवारी के भीतर सिमट गए हैं, अक्सर केवल झंडाई रूत तक।

मेरे बचपन में ही चुनावी दुखार का पैमाना चुनावी रैलियां हुआ करती थी। नेता आपकी पसंद की पार्टी का हो या नहीं, सारा शहर उसके भाषण को सुनने और उसकी रैली देखने जाया करता था। रैली में जुटी भीड़ और जनता की प्रतिक्रिया से ही चुनावी हवा का अनुमान लगाया जाता था। इस मायने में भी भारत का चुनाव यूरोप और अमरीका से बहुत अलग था, जहां नेता जनसमूहों के सिर्फ टीवी, कैमरे के लिए करते थे। फिर-थीरे हम भी उसी राह पर चल निकले हैं। चुनाव रैलियों से टटकर अब टीवी के पर्दे पर खिस्क आया

दलों में भी विल्कुल हाशिए पर खड़े नेता किया करते थे। पिछले 10 वर्षों में संवैधानिक पदों पर विराजमान नेताओं ने भी इस भाषा की मर्यादा को तोड़ने में अग्रणी भूमिका अखियावर कर ली है। हर चुनाव में ही खास दिन दोगुना, रात चौगुना बढ़ता जा रहा है। पहले कभी-कभार ऐसा राजनीतिक कार्यक्रमों का दिन था, जो नाम मात्र के पैसे खर्च कर चुनाव जीत जाता था। अब ऐसे अपवाद हूंदने पर भी नहीं मिलेंगे। विधानसभा चुनाव में चुनावी खर्च की सीमा भले ही 40 लाख रूपए हो, लेकिन हर गरीब उम्मीदवार असलान 5-10 करोड़ रूपए खर्च करने पर मजबूर है। सम्पन्न राज्यों में यह राशि 25-30 करोड़ रूपए है तो कुछ शहरी सीटों पर 50 करोड़ रूपए या उससे भी अधिक है। जरूरी नहीं कि लोग पैसा लेकर उसी उम्मीदवार को वोट डालेंगे लेकिन अब देश के अधिकांश इलाकों में वोटर भी चुनावी दक्षिण को अपना अधिकार मानता है।

मीडिया कभी भी चुनाव में पूरी तरह निष्पक्ष नहीं था, लेकिन आज की तरह सत्ता की गोदी में नहीं था, सत्तारूढ़ पार्टी के मौजूदा का काम नही था, विपक्षी दलों और नेताओं का भेड़िए की तरह शिकार नहीं करता था। पहले चुनाव परिणाम टैटल के तहत सुनाते हुए आते थे, अब वे भी टी-वी ट्यूबों की रफ्तार से टीवी के पर्दे पर आते हैं। मोकदमाली-गोचर, अंगरंगल आरोप और मड़काड़ भाषा का इस्तेमाल विपक्षी

रोजगार के संदर्भ में बदलाव होगा नजरिया

—प्रहलाद सबनानी—

भारतीय प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति की सदस्य सुश्री शमिका वरे द्वारा हाल ही में सम्पन्न किए गए एक रिसर्च पेपर में, आंकड़ों के साथ, कई महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। इस रिसर्च पेपर में भारत के आर्थिक विकास के कई क्षेत्रों के सम्बन्ध में गहन विश्लेषण सागरमिति बाते बताते के साथ साथ यह भी जानकारी दी गई है कि किस प्रकार भारत में अब ग्रामीण इलाकों की देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान बढ़ा रहे हैं तथा कई राज्यों की आर्थिक स्थिति में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही, यही बताया गया है कि किस प्रकार भारत में गति से हो रहे आर्थिक विकास का लाभ देश के युवाओं को रोजगार के अधिक अवसरों के रूप में मिल रहा है।



राष्ट्र है, बरकरार यह ध्यान लिए कि इन बड़े हुए खर्चों के लिए क्या उन्कन प्रकार के बड़े हुए खर्च इन राज्यों के बजट पर अंततः दबाव बढ़ाते हैं। आज देश में कुछ राज्यों में व्याज के मुनाफा, प्रवासन सम्बन्धी खर्चों एवं सेवायुक्त कर्मचारियों को पेशन का मुनाफा करने में ही पूरे बजट की रकशि समाप्त हो जाती है। प्रदेश में विकास कार्य करने के लिए कुछ की राशि बचती ही नहीं है बल्कि कुछ राज्यों को तो इन मदों पर मुनाफा करने हेतु भी ऋण लेना होता है जो बजट पर और अधिक दबाव को बढ़ाता है। पूँजीगत खर्च इन राज्यों में कम ही हो पा रहे हैं जिससे इन राज्यों में प्रति व्यक्ति आय भी कम है एवं ये राज्य विकास की दर को हासिल नहीं कर पा रहे हैं। दिल्ली में पिछले 10 वर्षों तक पूँजीगत मदों पर बजट का एक बहुत बड़ा भाग खर्च होता था परंतु पिछले 10 वर्षों में पूँजीगत व्यय में भारी कमी घटितगोचर हुई है। पंजाब की स्थिति भी बहुत खराब हो गई है केवल 20 वर्ष पूर्व तक पंजाब देश में सबसे अमीर राज्यों की श्रेणी में शामिल था परंतु आज इससे अपसमर के राज्य, हिमाचल प्रदेश एवं हरियाणा भी पंजाब से आगे निकल गए हैं इन राज्यों में उद्योगों को स्थापित करने की आज सबसे अधिक आवश्यकता है। पंजाब से उद्योग निकलकर हिमाचल प्रदेश एवं हरियाणा में चलना गया है। मध्यप्रदेश एवं बिहार कुछ के क्षेत्र में बहुत भारी बुद्धि दान कर रहे हैं परंतु उद्योगों के कम मात्रा में होने के चलते इन राज्यों में प्रति व्यक्ति आय में बुद्धि दर तुलनात्मक रूप से कम है।

किंसी भी देश के लिए अम की भागीदारी एवं बेरोजगारी उद्योग अलग मुद्दे हैं। अम की भागीदारी से 18 वर्ष से 68 वर्ष के बीच के वेलो शमिल करने हैं जो आर्थिक अर्जन हेतु या कोई आर्थिक कार्य करने हैं अथवा कोई कुछ कार्य करने को उत्कृष्ट है एवं इनसे उद्योग ताला रहे हैं। पिछले 40 वर्षों के दौरान जीन में अम की औसत भागीदारी 73 प्रतिशत से ऊपर रही है। अर्थात् प्रत्येक 4 में से 3 लोग या तो रोजगार में रहे हैं अथवा रोजगार तलाश रहे हैं। विधानमंडल में अम की भागीदारी 72 से 73 प्रतिशत की बीच रही है। बांग्लादेश में यह 60 प्रतिशत से अधिक रही है। परंतु भारत में अम की

प्रदूषण की गिरफ्त में जिन्दगी



—निर्मल रानी—

उत्तर भारत का एक बड़ा क्षेत्र इन दिनों 'स्मॉग' यानी जहरीले धुये युक्त कोहरे जिसे घूम कोहरा भी कहा जाता है, की चपेट में है। यह कोई पहला अवसर नहीं है जबकि रसमों यानी जहरीले धुये की खबरें मीडिया में सुर्खियां बटोर रही हो। बल्कि लगभग दो दशक से यह स्थिति प्रत्येक बड़े पैदा हो रही है। हों दिल्ली जल्द ही कि प्रदूषण दिन प्रतिदिन और भी न केवल बढ़ता जा रहा है बल्कि और भी जहरीला भी होता जा रहा है। इसका घोर प्रदूषण युक्त वातावरण का खामियाखता हमें तरुन तख्त से मुगलता पड़ रहा है। कहीं विमानों की उड़ानें प्रभावित हो रही हैं तो कहीं ट्रेंस परिव्यालन में बाधा आने के चलते रेल गाडियां रुक रही हैं। मत दिनें खराब मौसम के कारण ही दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर 15 विमानों का मार्ग बदला गया जबकि 100 से अधिक उड़ानों में देरी हुई। सड़कों पर दुर्घटनाओं में इजाफा होना लगा है। स्वास्थ्य कार्णों से बच्चों के स्कूल बंद कर दिए जाते हैं तो अस्पतालों में सांस और दमा के मरीजों की संख्या बढ़ जाती है। यहाँ तक कि एक स्वस्थ व्यक्ति भी ऐसे वातावरण में सांस लेने में दिकत महसूस करने लगता है। लोगों को खुजली हो रही है और आंखों में जलन व आँखों से पानी आने की शिकायतें आ रही हैं। मास्क लगाना या न लगाना दोनों ही स्थिति में लोगों को परेशानी हो रही है। पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी बढ़ते प्रदूषण की वजह से हालात गंभीर बने हुए हैं। पिछले दिनों पाकिस्तान के लाहौर में स्थान यानी जहरीले धुये की इतनी मोटी चादर बिछ गई जो ऑनरिश को भी दिखाई देने लगी।

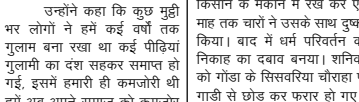


आज खबर तो यहां तक है कि स्थानी जहरीले धुये से पैदा होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए पड़ोसी देशों में जाकर धुये को जलाने के लिए फैलाया जा रहा है। जहाँकि उद्योग फैलाते हैं जिम्मेदार बहानों की संख्या प्रतिदिन लाखों की तादाद में बढ़ती जा रही है। उद्योगों से प्रदूषित धुआं नितर निकलता रहता है। पूरे देश की सड़कों धुल मिट्टी से ढेरी पड़ी है। खेतों में फसलों के अवशेष बेरोकटो जलाने का चलन रहा है। जगह जगह आम लोग कुड़े के ढेर में बेबीफ होकर आम लोग लाते हैं जिन्हें रबड़,पॉलीथिन,प्लास्टिक आदि सब जगह जलाया जाता है। इसी तरह आदिवासी बचाने के लिये बांधें अदालतें मना कर पा सरकारों कोई भी मानने को तैयार नहीं। बल्कि हर साल आदिवासी का चयन व इनकी खपत बढ़ती ही जा रही है। यद्यपि आम दीवारली पर आदिवासी बचाने को लेकर उद्घाटन देने लगे तो समझो आप को समानत तरीकी हमें को प्रमाण पत्र तो उसी ढंग मिल जायेंगा। गुरुपूर्व पर होने वाली आदिवासी पर सवाल उठाया तो

शुरूआत में हमेशा टी वी व अखबारों में यह सुर्खियां बनती थी कि प्रदूषण का स्तर क्या है। विशेषज्ञों के अनुसार स्वच्छ हवा वाले वातावरण के लिये 50 फी.फा.होना चाहिए। 50 से कम (फुफ.एयर प्वालिटी इंडेक्स) है, जहरीला धुआं,एक लेवा प्रदूषण,स्मॉग यानी जहरीले धुये युक्त कोहरे की चादर और अतंत बदलती मौसम व 'लीबल वालिग'।

जिसतरह बारिश के दिनों में शहरों में समुचित जल निकासी का प्रबंध न होने के चलते शहरों व कस्बों में बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है और इससे संबंधित खबरें लेख व परिचर्चाओं में ऋतू के दौरान पड़ने सुनने को मिलती है। परन्तु बारिश खत्म होते ही जगह जगह व सरकार समी हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं और आगले साल की बारिश व इससे होने वाली तबाही की प्रतीक्षा करने लगते हैं। ठीक उसी तरह हर साल दीवारली के बाद और सर्दियों के आगाल में हर वर्ष यही प्रदूषण व जहरीले धुये की चर्चा सुर्खियों में आ जाती है। इस विषय को लेकर हमें अंतर्राष्ट्रीय की जागरूकता व समझ का अंशजा इसी बात से लगाना जा सकता है कि न तो कोई अतिशयभारियों से परहेज के लिए तैयार है न ही यह मानने के लिये तैयार है न ही जहरीला या खेतों में फसलों के अवशेष पड़ने को प्रदूषण फैलता है। वनाबन्ध या वन धाबन्ध लोग मात्र एक सारी के साथ सफाई कर कर दीवारें फिरते हैं। सड़कों को व व बेरोकटो 6 आा करना तो लोगों के मौलिक अधिकारों में शामिल हो गये हैं। यहाँ तक कि रोजगार का कई जगह खुरा नगर पालिका के कर्मचारी झाडू देने के बाद जगह जगह इकट्ठा करने को पुरे कुड़े के ढेर में अपने ही हाथों से माफिस लगा देते हैं। गोया पड़ा दिखा हो या अनपढ़,पंडित हो या अमीर,वैद्यक वरत पर प्रदूषण बढ़ने के लिये समी जिम्मेदार हैं। इसलिये मने ही सतही विचार किने हो कि क्यों न लिये जाएं परन्तु हमको तब तो यह है कि 'स्मॉग प्रदूषण' अब एक लाईलाज संकट बन चुका है।

नेपाल में खपाई जा रही थी डीएपी, पकड़ा गया गोदाम सीज



नहीं जड़े जायेंगे। उन्हींके नामों का कमेजोर नहीं होवे देना है। उन्हींके नामों का कि हमें हमारे समाज में उजो कमजोर है उसे नासूर बनने के पहले समाप्त करना होगा तभी हम सशक्त रहेंगे

सन्तानमात्रां महाप्राज मुख्यान्तरं
सन्तानमात्रं अतिथिषां का स्यात्गतं
सत्करं कियत्।

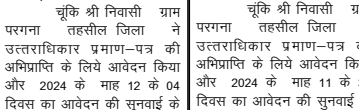
श्री राजगोपुस्रम अनामिका
के बाबू मुख्यान्तरं गोप्ति आत्यन्तिका
न के कश्चि प्रीतिवर्धनी त्रेता मुद्रा
संभवान्मात्रं सत्सं जुद्धा हेतु
भवान्मात्रं श्री गोपु न के विद्या सत्सं
के बाबू इत्येव गोप्ति का स्यात्गतं
यत्स्वप्न देवरात्रा बाबा सत्सं जुद्धा
हेतुः कियत्। उन्हेनो कश्चि फलते मन्त्र
आते ये तत्करा साराया बाबू
देहात्तरने सं चीडरा रोदो
नहीं होतः। उन्हेनो कश्चि इम सत्सं
को गो 500 यत्सं का संस्थता यत्सं
देवरात्रा की फलता के सत्सं पूरे देवरा
न के गो प्रामादनी के नेतुते म् गो
न के पूरा होतः। उन्हेनो कश्चि फल
कि इम कश्चि के लितः लाया लोगो
का बलिदान हुनः हे इमारी कश्चि
पीडित इम हातन कश्चि को नहीं

19 दिन की ब
गन्ने के खेत में



संबाददाता-बलरामपुर : सोहेलतला मुस्लिम प्रभाव के बुरहानपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चंबापुरा के मजदूर खेरनिमा में मंगलरात्रि के रात तंदुआ 19 दिन की बच्चों को उठा ले गया। वरु भिमाग की बच्चा मजदूर है। हरिया धारा क्षेत्र के देवास गांव निवासी चिरी प्रसाद खेरनिमा गांव के पास भी बच्चा मजदूर के रूट पर तंदू लगाकर रहता है। आसपास के गांवों में मिमलुत कृषक है। चिरीदा प्रसाद देवास की मंगलरात्र रात करीब एक बजे काज 19 दिन की नजवात बच्चे काजल तथा चिरी गीता के साथ तंदू कनात में सोया हुआ तनी अचानक ज्वाली जामनर उठकर 19 दिन की नजवात बच्चे को उठकरा के क्षेत्र में भाग गया। सूचना मिलते ही रेंजर राकेश पादक, वनजीवी शक आश्रीष सिधु द्वारा प्रहरी जांच की रही है। उपर प्रहरीग वनाधिकारी एसी सिधु ने

प्रतिभूतियों का वसूल करने के लिये उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की अभिप्राति के लिये प्रार्थना—पत्र के अन्तर्गत धारा 372 अधिनियम संख्या 39 सन 1925 ई०।



पंकज और मुकेश सहित अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। शोरूम की इलेक्ट्रॉनिक स्टोर को उठाया गया और विकसाल रूप बाणन किए हुए ली। मौके पर मृत्युस्थान की वातावरण, नानापाय और केसरों जैसी एक-एक कुल सात दमकल वाहन और बुझने में लगे हुए। शुक्राने ने बताया आज से उनका लगभग दो करोड़ रूपए का नुकसान हुआ है। चार दिन पहले ही 6000 लाईफ गार्ड्स की जो जेलकर हों खाता हो गया है। शोरूम आशीष और नवनीत के नाम पर है। खबर मिलते ही उनके दमकलकर्मी आज बुझा में जुटे हुए हैं। सौएफ्रो गोड विशाल रामानुज ने बताया आज निमित्त कारणों की वजह से लगी है जांच की राह रही है।

आज दिनांक माह सन ई० को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा सहित जारी किया गया। द० हाकिम	आज दिनांक माह र ई० को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा सहित जारी किया गया। द० हाकिम
---	--

आज दिनांक माह सन को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय मुद्रा सहित जारी किया गया। द० हाकिम	मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा सहित आज सन 20 के माह के दिवस क निकाली गयी। द० हाकिम
---	---

बसखत मेरे दस्तखत अँ
मुहर अदालत के आज बतारी
माह सन 20 ई0 जारी कि
गया।
—द0 हाकिम

जिसके जे ज्यदातर सभसँ सारह
 सहरक समितियाँ होएपी खाद
 नरदार हए। लेकिन निजी उर्वरक
 दुनोना पर डीपीनी उपबन्ध हए।
 दुनोनादार महंगे ठोह में खाद की
 बिक्री कर मानाला हो रहे हए।
 समितियाँ पर 1350 रुपये में मिलने
 वाली डीपीनी के लिए किसानों को
 डीपी दुनोना पर 1600 से 1800
 रुपये तक भुगतान करना पड़ रहै।
 तब सवाल यह हए कि जे
 समितियाँ पर डीपीनी नहीं होत
 डीपी दुनोना पर खाद कहाँ से उपबन्ध
 हो रहै। निजी दुनोना के संचादक
 दुनोना पर खाद न रखवत अरु
 अलग गोदाम में रखे रहै और सभ
 छिपे गोला को महंगे ठोह में डीपीनी
 बेंच रहै। डीपीनी न रखे से गन्नी
 की ब्याहँ गिरावट रहै। इससे किसानों

सह रूप से जाम हटवाया।
 किसानों का करना था कि सबिच
 मन्मानी नरुहो होएपी का वितरण
 नहीं कर रहे हए।

साधन सहरक समिति
 गुजरवाया में खाद उत्तरदा द्रव्य
 था जिसे देख कर किसान पृथक्
 गए। इसी तरह से किसान सभ
 समितियों के साधन सहरक समिति
 दुनोना में 340 बोरी डीपी मिली थी।
 जिसको लेने के लिए किसानों की
 भीड नंग रहै। इस पर सबिच ने
 पुलिस की मदद से टोकन द्वारा
 खाद का वितरण किया। इस मीक
 पर हकाने लेखाला सबिच शुक्ल वा
 सोनाप पुलिस के सिपाही मौजूद
 रहे। साधन सहरक समिति करिब
 भागी में डीपी खाद का वितरण हो
 रहै।

गया।	गया।
—द० हाकिम	—द० हाकिम

—द० हाकिम

bhartiyabasti@gmail.com